अपीलीय सिविल

प्रेम चंद पंडित न्यायाधीश और गोपाल सिंह न्यायाधीश के समक्ष

महंत शिव नाथ, ***अपीलकर्ता***

बनाम

पंजाब वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट, - ***प्रतिवादी।***

1968 की नियमित प्रथम अपील संख्या 28

28 सितंबर, 1971

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या V) - आदेश 6 नियम 17 और आदेश *23* नियम *1* - पंजाब न्यायालय अधिनियम (*1918* का *VI*) - धारा **39** - *संपत्ति के कब्जे* और खातों के प्रतिपादन के लिए मुकदमा - जूरी *के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकनदोनों राहतों का उच्चारण वाद में अलग-अलग निर्धारित किया गया है जिससे कुल मूल्य 10,000/- रुपये से अधिक* हो गया है। 10,000 **रुपये - वापस लिए गए खातों के प्रस्तुतीकरण के** *लिए राहत - वाद का क्षेत्राधिकार मूल्य - क्या कब्जे से राहत* **के लिए** *निर्धारित राशि तक स्वचालित रूप से कम हो गया है - वाद क्षेत्राधिकार मूल्य - क्या इसे संशोधित माना जाता है जिससे मूल्य 10,000 करोड़ रुपये हो जाता है।* 10,000 *रुपये जो कब्जे के लिए राहत की बात है - मुकदमे में पारित डिक्री के खिलाफ अपील - चाहे वह जिला न्यायाधीश के पास हो और उच्च न्यायालय के लिए न हो।*

यह माना गया है कि जहां संपत्ति के कब्जे और खातों के हस्तांतरण के लिए एक मुकदमे में, दोनों राहतों के संबंध में अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन वाद में अलग-अलग तय किया जाता है, जिससे कुल मूल्य 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है, और खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत वापस ले ली जाती है, तो अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्य स्वचालित रूप से वाद में कब्जे की राहत के लिए निर्धारित किए गए तक कम हो जाता है। जो कि 10,000 रुपये है। चूंकि खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत को छोड़ दिया गया है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से वाद में उल्लिखित अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद के मूल्यांकन के लिए वाद में संशोधन के बराबर है। इस तरह के मुकदमे में पारित किसी भी डिक्री के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश के पास होगी, न कि उच्च न्यायालय में।

श्री आर. पी. गैंद, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, अमृतसर के *दिनांक 30* नवम्बर, *1967 के आदेश से नियमित* प्रथम *अपील, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि वादी का मुकदमा सफल हो और वाद में संपत्ति के कब्जे के लिए राहत के संबंध में इसे डिक्री की जाती है और खातों के प्रस्तुतीकरण की राहत के संबंध में वाद को वापस ले लिया जाता है और लागत की वसूली की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी और वादी के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया।*

आर.सी. डोगरा, और एस। अपीलकर्ता की ओर *से अधिवक्ता डी. शर्मा।*

प्रतिवादी के लिए *आदमी, मोहन सिंह लिब्रहन, वकील।*

निर्णय

पंडित, न्यायाधीश -(ek) इस मामले में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं। पहला यह है कि अपील पर उचित अदालत-शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और दूसरा यह है कि अपील विद्वान जिला न्यायाधीश, अमृतसर के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी, न कि इस न्यायालय में, मुकदमे का क्षेत्राधिकार मूल्य 10,000 रुपये है।

(दो) दूसरी आपत्ति को पहली बार लेते हुए, यह देखा जाएगा कि वादी, पंजाब वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी ने दो राहतों की

महंत शिव नाथ *बनाम* **पंजाब वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट। (पंडित, जे।**

मांग की थी। वे खातों के लिए एक डिक्री चाहते थे और मुकदमे में संपत्ति के कब्जे के लिए भी। अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य से, उन्होंने खातों के लिए राहत का मूल्य 200 रुपये और कब्जे के लिए मूल्य 10,000 रुपये तय किया था। इस प्रकार अधिकार क्षेत्र के लिए कुल मूल्य 10,200 रुपये था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान, जब मामला बहस के लिए परिपक्व था, वादी के वकील ने एक बयान दिया कि उनके मुवक्किल ने "खातों से संबंधित मुकदमा वापस ले लिया है"। हालांकि, इस मामले में मुद्दा संख्या 5 पहले ही तय किया जा चुका था और यह था- "क्या प्रतिवादी लेखा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है?" मुद्दा संख्या 5 के तहत अपील के तहत फैसले में, विद्वान ट्रायल जज द्वारा दिया गया निष्कर्ष था- "खातों के लिए मुकदमा वापस लेने के मद्देनजर, यह मुद्दा निरर्थक हो गया है। विद्वान न्यायाधीश ने तब संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन इसे वापस लिए गए खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए खारिज कर दिया। इस डिक्री के खिलाफ, वर्तमान अपील इस अदालत में महंत शिव नाथ, प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी।

(तीन) प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत वापस लेने के बाद मुकदमे का अधिकार क्षेत्र मूल्य 10,000 रुपये तक कम हो गया था और ऐसा होने पर, अपील अमृतसर के जिला न्यायाधीश की अदालत में दायर की जानी चाहिए थी। यह सामान्य आधार है कि यदि मुकदमे का क्षेत्राधिकार मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो अपील जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थापित की जानी चाहिए, न कि इस अदालत में।

(चार) दूसरी ओर, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार मुकदमे का क्षेत्राधिकार मूल्य 10 * 200 रुपये तय किया गया था, तो इसे बाद में वाद के संशोधन को छोड़कर कम नहीं किया जा सकता था, और ऐसा होने के नाते, अपील इस न्यायालय में सही ढंग से दायर की गई थी, लेकिन वाद में संशोधन नहीं किया गया था। वह आगे तर्क देते हैं कि वाद में संशोधन करके दावा की गई राहतों में से एक को छोड़ने और वापस लेने या वापस लेने के बीच बहुत अंतर है।

आदेश 23, नियम 1, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत किसी के दावे के एक हिस्से को छोड़ना। पहले मामले में, इसे इस तरह से लिया जाएगा जैसे कि वह राहत अपनी स्थापना से ही वाद में नहीं थी और इसलिए, इसके बारे में पार्टियों के बीच कोई परीक्षण नहीं था। बाद के मामले में, हालांकि, यदि कोई वादी दावे के उस पैन के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की अनुमति के बिना अपने दावे का एक हिस्सा वापस ले लेता है या छोड़ देता है, तो उसे भविष्य में उस दावे के संबंध में एक और मुकदमा दायर करने से रोक दिया जाएगा। इस मामले में, वादी में संशोधन के बाद खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन वादी के वकील ने केवल एक बयान दिया कि उसने खातों से संबंधित मुकदमा वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल जज ने उस राहत के संबंध में मुकदमा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि - "खातों के प्रस्तुतीकरण की राहत के संबंध में मुकदमा वापस लिया जाता है। चूंकि वादी द्वारा इस राहत को वापस लेने के लिए अदालत की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए वादी को भविष्य में इस राहत के संबंध में एक नया मुकदमा शुरू करने से रोक दिया जाएगा। यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खातों से संबंधित मुकदमे को वापस लेने से, वाद को स्वचालित रूप से उस संबंध में संशोधित किया गया था, जैसा कि वकील का तर्क है, तो वादी भविष्य में भी इस राहत के संबंध में एक और मुकदमा लाने का हकदार होगा। इसलिए, वकील का कहना है कि इस न्यायालय को यह नहीं कहना चाहिए कि वाद में स्वचालित रूप से संशोधन किया गया था और इस प्रकार वादी को भविष्य में इस राहत के संबंध में एक और मुकदमा लाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब ट्रायल जज ने अपने फैसले में विशेष रूप से कहा था कि मुकदमे को वापस ले लिए जाने के रूप में खातों के प्रस्तुतीकरण की राहत के संबंध में खारिज कर दिया गया था।

(पाँच) हमने पक्षकारों के वकीलों को कुछ विस्तार से सुना है क्योंकि माना जाता है कि इस मुद्दे पर किसी न्यायालय का कोई प्रत्यक्ष प्राधिकार नहीं है। अपीलकर्ता के वकील की दलील *प्रथम दृष्टया* प्रशंसनीय प्रतीत होती है, क्योंकि तथ्य यह है कि खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत के संबंध में वाद में वास्तव में संशोधन नहीं किया गया था। इसके अलावा, निस्संदेह वाद के संशोधन के परिणामों और दावे के एक हिस्से के संबंध में मुकदमा वापस लेने के बीच अंतर है। चूंकि वाद में वास्तव में संशोधन नहीं किया गया था, विशेष रूप से इसके पैरा 8 के संबंध में, जहां अधिकार क्षेत्र के उद्देश्य के लिए वाद का मूल्य दिया गया था, कोई भी वकील अपने मुवक्किल को इस न्यायालय में अपील दायर करने की सलाह दे सकता था, जिसमें उल्लिखित क्षेत्राधिकार मूल्य 10,000 रुपये से अधिक है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि इस मामले की परिस्थितियों में, कौन सा था

अपील दायर करने के लिए उचित मंच। यह सच है कि इस मामले में वाद में कोई संशोधन नहीं किया गया है और ट्रायल जज ने अपने

फैसले में खातों के प्रस्तुतीकरण की राहत के संबंध में मुकदमा खारिज कर दिया है और बाद में यह मुद्दा उठ सकता है कि क्या इस फैसले के सामने, वादी उसी राहत के संबंध में एक और मुकदमा ला सकता है; लेकिन यह विचार, मेरी राय में, हमारे सामने प्रश्न को निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक है। यह वकील को इस अदालत में अपील करने के लिए मुवक्किल को सलाह देने का आधार दे सकता है, लेकिन इस मामले में कुछ स्वीकृत तथ्य हैं, जो मेरी राय में, इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वाद को मुकदमे के अधिकार क्षेत्र के मूल्य के संबंध में संशोधित माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान वादी ने खातों के प्रस्तुतीकरण के लिए राहत छोड़ दी थी, जैसा कि 29 नवंबर 1967 को दिए गए उनके वकील के बयान से स्पष्ट होगा। यह भी निर्विवाद है कि वादी द्वारा खातों के लिए राहत के संबंध में अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मूल्य अलग से 200 रुपये तय किया गया था। चूंकि उस राहत को छोड़ दिया गया था, इसलिए संपत्ति के कब्जे के संबंध में मुकदमे के अधिकार क्षेत्र का मूल्य, इसलिए, मेरे विचार में, स्वचालित रूप से 10,000 रुपये तक कम हो गया था। यह स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे के मूल्यांकन के संबंध में वादी के संशोधन के बराबर होगा, जैसे कि वादी द्वारा मौखिक प्रार्थना की गई है। इसके अलावा, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डिक्री-शीट में भी, अधिकार क्षेत्र के लिए मूल्य 10,000 रुपये का उल्लेख किया गया था।

(छः) इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि इस मामले में अपील अमृतसर के विद्वान जिला न्यायाधीश की अदालत में दायर की जानी चाहिए थी। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अपील का ज्ञापन अपीलकर्ता को उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाए।

दो)ज) जहां तक अदालत-शुल्क के संबंध में आपत्ति का संबंध है, इसे विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा भी लिया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है, जो अपील की सुनवाई करेंगे,

आठ) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

गोपाल सिंह, जे-मैं सहमत हूं।

नौ) *एस.जी.*

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अमृतबीर कौर
प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी
अससंध, कर्नल
हरियाणा